संपादकीय जागरण

रविवार, 27 मई, 2018 : ज्येष्ठ शुक्ल 13 वि. 2075

विनम्रता सभी गुणों में श्रेष्ठ है

चुनावी वर्ष

इस पर हैरत नहीं कि जब सत्तापक्ष के नेताओं की ओर से मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं तब विपक्ष की ओर से इस पर जोर दिया जा रहा है कि यह सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की मानें तो मोदी शासन के चार साल बाद देश बेहाल है। उसने इस मौके पर विश्वासघात दिवस का आयोजन कर सरकार के दावों को झूठा बताने की भी कोशिश की। निःसंदेह कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन जैसे यह नहीं कहा जा सकता कि मोदी सरकार सभी मोर्चों पर सफल रही है और उसने अपने सारे वादे पूरे कर दिए वैसे ही यह बात भी गले नहीं उतर सकता कि उसने कुछ किया ही नहीं और उसके कारण देश समस्याओं की गर्त में चला गया है। चूंकि मोदी सरकार के कार्यकाल के चार साल पूरे होने के साथ ही आगामी आम चुनाव सत्तापक्ष और विपक्ष की प्राथमिकता में आ गए हैं इसलिए आने वाले समय में दोनों पक्षों का चुनावी मूड-माहौल में नजर आना स्वाभाविक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि उनके तेवर राजनीतिक माहौल में कटुता घोलने का काम करें। दुर्भाग्य से फिलहाल ऐसा होता ही दिख रहा है। यदि चुनावी वर्ष में राजनीतिक दलों की एक-दूसरे के प्रति आक्रामकता बढ़ती है जिसके कि आसार दिख रहे हैं तो फिर संसद में वैसी ही परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जैसी पिछले सत्र में देखने को मिली थीं और जिसके चलते वहां कोई उल्लेखनीय कामकाज नहीं हो सका था। देश के चुनावी वर्ष में प्रवेश कर जाने का यह अर्थ नहीं कि संसद राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो जाए और वहां जरूरी काम भी न हो सकें। बेहतर हो कि राजनीतिक दल राजनीति करने के अपने तौर-तरीके बदलने पर गंभीरता से ध्यान दें। इसलिए और भी, क्योंकि वे अपने आचार-व्यवहार से जिस आम जनता को प्रभावित और आकर्षित करने की कोशिश में दिन-रात एक करते हैं वह कहीं अधिक परिपक्व हो चुकी है।

पक्ष-विपक्ष को कम से कम राष्ट्र हित के अहम मसलों पर तो समझ-बूझ कायम करनी ही चाहिए। आखिर जब दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों में ऐसा हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? विडंबना यह है कि अब हमारे राजनीतिक दल विदेश नीति जैसे मसले पर भी संकीर्ण राजनीति करने से बाज नहीं आते। हालांकि राजनीतिक दल इससे अच्छी तरह अवगत हैं कि कोई भी सरकार हो वह चार-पांच वर्ष में इतने बड़े देश की सभी समस्याओं को नहीं सुलझा सकती, लेकिन जहां सत्तापक्ष अपने वादों से ऐसी ही प्रतीति कराता है वहीं विपक्ष हर मसले को न केवल तूल देने की ताक में रहता है, बल्कि लोगों को बरगलाने की भी कोशिश करता है। क्या सत्तापक्ष और विपक्ष ऐसे कुछ मुद्दों का चयन नहीं कर सकते जिन पर तू तू-मैं मै करने के बजाय आम सहमति से आगे बढ़ा जाए? यह ठीक नहीं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था आम सहमति की जिस राजनीति की मांग करती है उसका अभाव बढ़ता ही जा रहा है। यह अभाव तो देश की समस्याओं को बढ़ाने का ही काम करेगा।

पुलिस सुधार

पुलिस महानिदेशक का यह संकल्प स्वागत योग्य है कि भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, इसे अमल में लाना किसी चुनौती से कम नहीं है। डीजीपी भले ही पुलिस की कार्यप्रणाली बदलने को प्रतिबद्ध हों, सिटिजन फ्रेंडली एप सिस्टम शुरू कर रहे हों, पर पुलिस सुधार का यह रास्ता आसान नहीं है। पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार के लिए अभी तक गठित विभिन्न आयोगों के सुझावों पर अमल न हो पाने की बात छोड़ भी दें, तो ऐसी बहुत सी खामियां हैं जिनका लाभ भ्रष्ट पुलिसकर्मी उठाते हैं। पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज न करना, दूसरे पक्ष से हमसाज होकर पीड़ित की रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई न करना, क्षेत्र में अवैध कार्यों को होने देना, उगाही, आम जनता से दुर्व्यवहार आदि की घटनाएं भी इसीलिए होती हैं।

पहली जरूरत है आम जनता को डिजिटल प्लेटफार्म मुहैया कराना, जहां लोग शिकायत दर्ज करा सकें

फिलवक्त पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार के लिए पहली जरूरत है आम जनता को डिजिटल प्लेटफार्म मुहैया कराना, जहां लोग शिकायत दर्ज करा सकें। शिकायतों पर कार्रवाई क्या हुई उच्च स्तर पर इसकी निगहबानी भी जरूरी है। वस्तुतः पुलिस को जवाबदेह और जिम्मेदार तभी बनाया जा सकता है। आधुनिकीकरण के नाम पर केवल नई गाड़ियां और अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध करा देने से ही काम नहीं चलने वाला है, बल्कि पुलिसकर्मियों को तमाम मामलों में संवेदनशील बनने की सीख देनी पड़ेगी। पुलिस व्यवस्था को जितना ही पारदर्शी बनाया जाएगा, उतना ही सुधार आएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो पुलिस हेल्मेट न लगाने वाले दुपहिया चालकों के खिलाफ अभियान चलाती है। जुर्माने से प्राप्त धनराशि को पुलिस आखिर सीसीटीवी कैमरे लगाने और ई-चालान की व्यवस्था पर खर्च क्यों नहीं करती। सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एक स्थायी दस्ता आखिर गठित क्यों नहीं किया जाता, जिसका काम पूरे शहर में घूमकर अतिक्रमण करने वालों का चालान काटना होना चाहिए।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आप मोदी सरकार के चार साल के कामकाज से संतुष्ट हैं?

आज का सवाल
मोदी सरकार के चार साल के कार्यकाल के दौरान क्या विपक्ष ने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

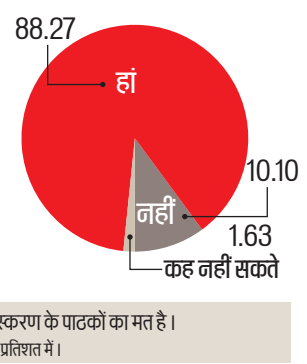

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

मोदी की उपलब्धियां और चुनौतियां

डॉ. एके वर्मा

मोदी की खासियत उनकी कार्य निष्ठा, साफ-सुथरी छवि और सामाजिक विकास है, लेकिन उन्हें जनता को चार वर्षों का रिपोर्ट कार्ड देने के साथ भावी रोडमैप भी बताना होगा

नरेंद्र मोदी सरकार के चार वर्ष पूरे हो गए और वह 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसती दिख रही है। चार साल की क्या उपलब्धियां रहीं मोदी सरकार की और चुनावी वर्ष में उसके सामने कौन-कौन सी चुनौतियां होंगी, इस पर विचार करते समय इस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि मोदी के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों ने अपने-अपने कार्यकाल में क्या किया था और आगामी लोकसभा चुनाव में जनता के पास क्या विकल्प होंगे? जहां मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने की जिम्मेदारी सरकार, भाजपा और उसके जनप्रतिनिधि उठा रहे हैं वहीं कांग्रेस मोदी सरकार के चार साल पूरा होने को 'विश्वासघात' के रूप में मना रही है। ऐसा करने का उसे संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह देखना दिलचस्प है कि बीते चार वर्षों में मोदी ने ऐसा क्या नहीं किया जो पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों ने किया था? मोदी का पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह 'मौन' नहीं रहे। उन्होंने जन संवाद की शैली अपनाई। देश में 'मन की बात' और विदेश में अप्रवासी भारतीयों से संवाद कर उन्होंने 'मौन शैली' को तोड़ा। इससे लोगों को लगा कि वे उनके प्रधानमंत्री हैं। जनता ने उनके काम की प्रशंसा और आलोचना, दोनों की, लेकिन वह लोगों से और लोग उनसे जुड़े रहे। लोगों को मनमोहन सिंह के निर्णय उनके अपने कम और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अधिक लगते थे। मोदी के निर्णयों पर न तो पार्टी अध्यक्ष और न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निर्देशित होने की बू आती है। उनके प्रत्येक निर्णय पर सशक्त प्रधानमंत्री की छाप रहती है। नोटबंदी का फैसला इसका ज्वलंत उदाहरण है। इस फैसले से मजबूत प्रधानमंत्री की छवि वाले मोदी पर जनता भरोसा बढ़ा। 1991 में जब कांग्रेस के शासन में प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने अपने तत्कालीन वित्तमंत्री मनमोहन सिंह के माध्यम से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की तो भारत की अर्थव्यवस्था खूब फली-फूली; विदेशी निवेश, विदेशी मुद्रा भंडार और निर्यात आदि काफी बढ़े, लेकिन वे आर्थिक सुधार विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के दबाव में शुरू किए गए थे।

इसके विपरीत मोदी के आर्थिक सुधार विदेशी संस्थाओं से निर्देशित नहीं, वरन उनकी अपनी सोच से जन्में। इनमें कालेधन की स्वघोषणा, विमुद्रीकरण, जीएसटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा और गोल्डबांड जैसे कई प्रयोग प्रमुख रहे। इनकी आलोचना भी हुई, लेकिन उन्हें जन समर्थन भी मिला। अब उनके बेहतर परिणाम आ रहे हैं। रिजर्व बैंक और आयकर विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार चार वर्षों में उपभोक्ता सूचकांक आधारित महंगाई आठ प्रतिशत से घट कर चार प्रतिशत, डिजिटल लेन-देन 663 करोड़ से बढ़ कर 20798 करोड़, 31 करोड़ जन-धन खातों में बचत बढ़ कर 81205 करोड़, करदाताओं की संख्या दो गुनी और कर आय 638 करोड़ से बढ़कर 995 करोड़ हो गई है। जाहिर है अर्थव्यवस्था में आने वाले इस सकारात्मक परिवर्तन का लाभ जनता को ही मिलेगा। इससे पिछले चार वर्षों में 25 लाख तक की वार्षिक आमदनी वालों का टैक्स कम और उससे ज्यादा वालों का टैक्स बढ़ गया है। क्या इसे सूट-बूट की सरकार कहें या गरीब और मध्यमवर्ग की चिंता करने वाली सरकार?

अवधेश राजपूत

मोदी सरकार ने वह नहीं किया जो मनमोहन सरकार के दो कार्यकालों की खासियत बन गई थी-भ्रष्टाचार और घोटाले। कांग्रेस को यह सब याद रखना चाहिए। मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत उसका भ्रष्टाचारविहीन और घोटालाविहीन कार्यकाल है। राज्यों के स्तर पर अभी वह संस्कृति नहीं आ पाई है, चाहे वहां भाजपा की सरकार हो या किसी और दल की। इसीलिए आम आदमी नहीं समझ पा रहा कि मोदी के आने से उसे भ्रष्टाचार से क्या राहत मिली? सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार उसी तरह फल-फूल रहा है। जनता को नहीं पता कि राज्यों, नगरपालिकाओं और पंचायतों के दफ्तरों में मोदी की नहीं, दूसरों की सरकारें हैं। यहीं से शुरू होती है मोदी और भाजपा की चुनौतियां।

राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने की कला ही नहीं, वरन उसे बनाए रखने की विधि भी है। चार वर्ष पूर्व मोदी ने जब सत्ता प्राप्त की थी उस समय उन्होंने विकास की अलख जगाई थी। उसी जनता को अब उन्हें संतुष्ट करना होगा। आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी प्रतिरक्षात्मक और विपक्ष आक्रामक रहेगा। यह चुनौती इसलिए और भी गंभीर हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष एकजुट होकर पुरजोर कोशिश करेगा कि भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिल सके और वह केवल सबसे बड़ी पार्टी होकर रह जाए। हाल में कर्नाटक प्रयोग से स्पष्ट हो गया कि सबसे बड़ी पार्टी के मुकाबले बहुमत वाले 'चुनाव पूर्व गठबंधन' को बुलाना राष्ट्रपति की बाध्यता होगी। देखना होगा कि भाजपा इससे निपटने की क्या रणनीति बनाती है?

मोदी की दूसरी बड़ी चुनौती यह होगी कि इतने बड़े देश में चुनाव-प्रचार कैसे चलाया जाए? इस बार उनके पास 2014 जैसी आजादी नहीं। वह देश के प्रधानमंत्री हैं और समस्त सरकारी दायित्वों का निर्वहन करते हुए ही उन्हें चुनाव-प्रचार में उतरना पड़ेगा। मोदी का कद बढ़ने से भाजपा में उन जैसा 'वोट मोबिलाइजर' और कोई नहीं। मोदी की तीसरी चुनौती यह है कि 2014 में ज्यादातर राज्यों में भाजपा का वोट प्रतिशत काफी अधिक था। क्या पार्टी वह प्रदर्शन दोहरा पाएगी, खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में? बिहार में पिछले चुनाव में नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ गए थे। क्या इस बार बदली परिस्थिति में भाजपा और बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी? कहीं विपक्ष नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में आगे करके चुनावी रणनीति में कोई आमूल-चूल परिवर्तन करने की तो नहीं सोच रहा? यह भी देखें कि भाजपा के सहयोगी दलों की क्या स्थिति है? शिवसेना, अकालीदल, अपना दल, सुहलदेव पार्टी आदि राजग में अपना हिस्सा बढ़ाने की जिद तो नहीं करेंगे? क्या भाजपा ने 2014 से अपने जनाधार में जो क्रांतिकारी विस्तार किया है वह उसे बचा पाएगी? क्या भाजपा गरीबों, किसानों, दलितों और पिछड़े वर्ग में अपनी पैठ बढ़ा सकी है? चंद्रबाबू नायडू के भाजपा से अलग होने से पार्टी के पास मौका है कि वह आंध्र प्रदेश में और सीटें जीत सके। 2014 में तेदेपा से गठबंधन के कारण वह कुछ सीटों पर ही चुनाव लड़ सकी थी और तीन सीटें एवं 5.8 प्रतिशत मत पा सकी थी। तमिलनाडु और त्रिपुरा भी ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा कुछ बेहतर कर सकती है। हालांकि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल और तेलंगाना में उसे अपनी उपस्थिति बढ़ाने में मुश्किल होगी। कुछ भरपाई पूर्वोत्तर के राज्यों से हो सकती है, लेकिन वहां सीटें बहुत कम हैं।

आज एक बड़ा सवाल यह है कि क्या संयुक्त विपक्ष मोदी के मुकाबले कोई चेहरा आगे कर सकेगा? यदि नहीं तो क्या राहुल गांधी कहीं दूर-दूर तक भी मोदी के मुकाबले ठहर सकेंगे? मोदी की खासियत उनकी कार्य निष्ठा, साफ-सुथरी छवि और सामाजिक विकास है। इसी कारण 2014 के बाद पार्टी ने कई नए राज्यों में विजय पाई, लेकिन आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें न केवल नेताओं और कार्यकर्ताओं से जुड़ना होगा, वरन जनता को चार वर्षों का रिपोर्ट कार्ड देने के साथ भावी रोडमैप भी बताना होगा।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पालिटिक्स के निदेशक हैं)

response@jagran.com

पक्ष-विपक्ष की खुशी का संयोग

हास्य-व्यंग्य

संतोष त्रिवेदी

सत्तापक्ष इससे खुश है कि अभी तो उसके पास 12 महीने हैं और विपक्ष यह सोचकर कि अब बस एक साल की ही देर है

बहुत दिनों बाद ऐसा संयोग आया, जब पक्ष-विपक्ष दोनों खुश दिखे। सत्ता-पक्ष के चार साल बीत गए तो वह इसे 48 महीने समझकर खुश है। उसके लिए विकास की यह लंबी यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। उसके पास अगले 12 महीने तो हैं ही। विपक्ष इसलिए प्रसन्न है कि उसके दुर्दिन समाप्त होने में केवल एक साल बचा है। लगातार कई हारों के बाद उसे कहीं-कहीं जीत नसीब होने लगी है। चार साल घोड़े बेचकर सोने के बाद आखिरकार उसे गठबंधन की 'पवित्रता' पर भरोसा हुआ। सत्ता की गठरी खुलने के लिए उसने आपस की सारी गांठें खोल दी हैं। इसलिए वह भी गदगद है।

कुल मिलाकर सभी सुखी और प्रसन्न हैं। यह इसलिए मुमकिन हुआ, क्योंकि हमारे सभी रहनुमा खुश हैं। कुछ नासमझ नागरिक जरूर हैं, जो इस ऐतिहासिक जश्न पर 'पेट्रोल' छिड़कना चाहते हैं। जो पढ़े-लिखे और समझदार लोग हैं वे तेल के शतक लगाने की बाट जोह रहे हैं। वे तभी जश्न मनाएंगे। सरकार के समर्थक तेल से होने वाले नुकसान गिना रहे हैं। इससे होने वाला प्रदूषण सड़क से निकलकर सोशल मीडिया तक फैल गया है। सारा तापमान उसी का है। तेल को इसलिए छुट्टा छोड़ा गया है ताकि जश्न के इस माहौल में तेल कंपनियों के कुएं भी लबालब हो सकें। इस जश्न का जमीनी जायजा लेने के लिए अपुन भी पूरी तरह तैयार हो गए। घर से बाहर निकलकर देखा तो आंखें चौंधियां उठीं। जगह-जगह जश्न की प्रदर्शनी लगी हुई थी। सबसे ज्यादा उल्लास 'चार साल बेमिसाल' वाले स्टॉल पर दिखा। जितनी जगह थी उससे ज्यादा बैनर टंगे थे। लग रहा था कि जगह और होती तो विकास और दिखता। स्टॉल के संचालक सामने ही दिख गए। बिल्कुल फिट लग रहे थे। जवाब देने के मूड में थे। हमने कहा, इससे हमारा काम बहुत हल्का हो गया है। अब हम आराम से बात कर सकते हैं। वे पुश-अप करते हुए बोले, 'तुम्हारा काम भले हल्का हो, हम कभी हल्का काम नहीं करते। जो भी पूछना है, जल्दी पूछिए, हमें जश्न मनाना है।'

'किस बात का जश्न मना रहे हैं आप?' हम सीधे मुद्दे पर आ गए।

वे ठहाके लगाने लगे और पूरे चार ठहाकों के बाद कहने लगे- 'जनता पूरी तरह हमारे साथ है। वह पिछले 48 महीनों से हमारे आश्वासन पर जीवित है। इसका भरपूर स्टॉक हमारे पास है। हम तो इतने उदार हैं कि विरोधियों को भी समुचित मात्रा में आश्वासन बांट रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें शासन चाहिए। इसलिए वे जनता को बांट रहे हैं। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमने जश्न की पुड़िया बनाई है, एकाध तुम भी लेते जाना। सवालों के चक्कर से निकलकर जश्न मनाने लगोगे।' इतना कहकर उन्होंने एक पुड़िया हमारी ओर बढ़ा दी।

पुड़िया लेने से पहले ही हम सवाल दाग चुके थे-'सुना है तेल के दामों को लेकर जनता में भारी असंतोष है। दाम इतना बढ़ क्यों रहे हैं?' हमारा प्रश्न सुनकर अंगुली से ग्राफ बनाते हुए वे समझाने लगे-हम चाहते हैं कि तेल की खपत कम हो। इससे ऊर्जा बचेगी। जनता के पास यह ऊर्जा संचित रहेगी तो अगली बार फिर हमारी सरकार बनेगी। इससे हमें ऊर्जा मिलेगी। हम और अधिक ऊर्जा से काम करेंगे। तेल जनता की पहुंच से जितना दूर होगा, पर्यावरण उतना ही शुद्ध होगा। इसीलिए हम जनता का बचा-खुचा तेल भी निकाल रहे हैं। तुम भी देशहित में सवाल पूछकर अपनी ऊर्जा नष्ट न करो, आगे बढ़ो।

हम उनका मंतव्य समझकर आगे बढ़ गए। सड़क के बीचोंबीच विपक्ष के प्रतिनिधि जश्न मनाने के मूड में तेल छिड़कने में लगे हुए थे। हमने सुलगता हुआ सवाल पूछ लिया, 'अरे भाई आप किस बात का जश्न मना रहे हैं?' वे पहले चिंगारी और फिर शोले की तरह भड़क उठे-आप किस मीडिया से हैं? आपको दिखता नहीं कि हम जश्न नहीं 'विश्वासघात दिवस' मना रहे हैं। यह सरकार सत्ता से तो पहले ही हमें बेदखल कर चुकी है, अब हम जैसे 'बंगला-पकड़' को बेघर करने पर भी तुली है। तेल देखो, तेल की धार देखो। असल आग तो सरकार ने हमारे बंगलों में लगाई है, लेकिन तुम्हें केवल तेल दिख रहा है, उसकी धार नहीं। आम आदमी तो एकबारगी बिना रोटी, कपड़े और मकान के रह लेगा। इसका उसे खासा तजुर्बा भी है, लेकिन उसका सेवक अगर सड़क पर आ जाए तो यह जनतंत्र के साथ विश्वासघात है।'

'तो क्या वह जश्न आपको सड़क पर लाने के लिए मनाया जा रहा है?' हमने कमजोर नस धीरे से दबा दी। वह करीब-करीब सुबकते हुए कहने लगे, 'इस बंगले से हमारी यादें जुड़ी हैं। यह हमारी जश्नगाह है। बहुत सारे जश्न हमने यहीं निपटाए हैं। हमारे वोटर को भी हमारा यही पता मालूम है। सरकार हमें लापता करना चाहती है ताकि हम पूरी तरह मुक्त हो जाएं। यह घोर विश्वासघात नहीं तो और क्या है?' सवाल के बदले सवाल सुनकर मुझे जश्न वाली पुड़िया की याद आ गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उसे खाऊं या न खाऊं?

response@jagran.com

ऊर्जा

क्रोध मुक्ति

क्रोध से अधिक विनाशक तत्व संसार में और कोई नहीं है। सभी यह जानते हैं, किंतु क्रोध रहित होने का दावा शायद ही कोई कर सके। क्रोध स्वयं में अवगुण नहीं है। यह अवगुणों की अभिव्यक्ति है। क्रोध न करने की बात करना पानी में डूब रहे व्यक्ति को तैरना सीखने का उपदेश देने जैसा है। आश्चर्य होता है कि क्रोध प्रबंधन पर व्यापक चर्चाएं हो रही हैं। कई पुस्तकें बाजार में हैं। कतिपय चिकित्सा पद्धतियों में इसकी दवा भी उपलब्ध है। यदि तैरना नहीं आता तो पानी में उतरने पर डूबने से कोई नहीं बचा सकता। यदि अवगुण हैं तो क्रोध रोकना असंभव है। मनुष्य को क्रोध तभी आता है जब सब कुछ उसके मन के अनुकूल नहीं होता। मनुष्य को धन, संपदा,पद, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा का भारी मोह होता है। जब भी इन पर आंच आती है वह क्रोधित हो उठता है। यहां क्रोध का मूल लोभ है। जब उसके परिजन, मित्र, संबंधी आहत होते हैं या उसे आहत करते हैं तब उसका क्रोध इनके प्रति मोह के कारण उपजता है। जब मनुष्य की कामनाएं अवरुद्ध होती हैं तब भी वह क्रोधित होता है।

जब तक मनुष्य मोह, लोभ, कामनाओं, वासनाओं के सागर में उतरता रहेगा क्रोध उसे डुबोने को तैयार रहेगा, क्योंकि यह संभव नहीं कि सदैव उसके मन की इच्छाएं पूरी होती रहें। सदैव उसका मनचाहा नहीं हो सकता। बहुत से मनुष्यों के साथ ऐसा होता है कि वे सफलताओं, उपलब्धियों के अभ्यस्त हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कामधेनु उनके हाथ लग गई है, किंतु वास्तव में यह भ्रम होता है। आज तक संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ। इसलिए जब असफलताएं सामने आती हैं, कामनाएं पूरी नही होतीं तो वे प्रचंड क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं।

मनुष्य क्रोध का नहीं लोभ, मोह, वासनाओं और अहंकार का प्रबंधन करना सीखे। मनुष्य जब इस बात पर विश्वास कर ले कि इस सृष्टि का सृजक और पालक ईश्वर है और सब कुछ उसी की इच्छा से हो रहा है तो उसे अपनी क्षुद्रता दिखने लगती है। मनुष्य के पास जो कुछ है वह ईश्वर का दान है। ईश्वर जब जो चाहे किसी भी निमित्त उससे वापस ले सकता है। इस विचार को मन में धारण करते ही लोभ, मोह, अहंकार, कामनाएं स्वयं ही तिरोहित होने लगती हैं। यह जीवन की सबसे बड़ी साधना है।

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह

तथ्य-कथ्य | किस ब्रांड की कितने लोगों तक पहुंच

(संख्या अरब में)

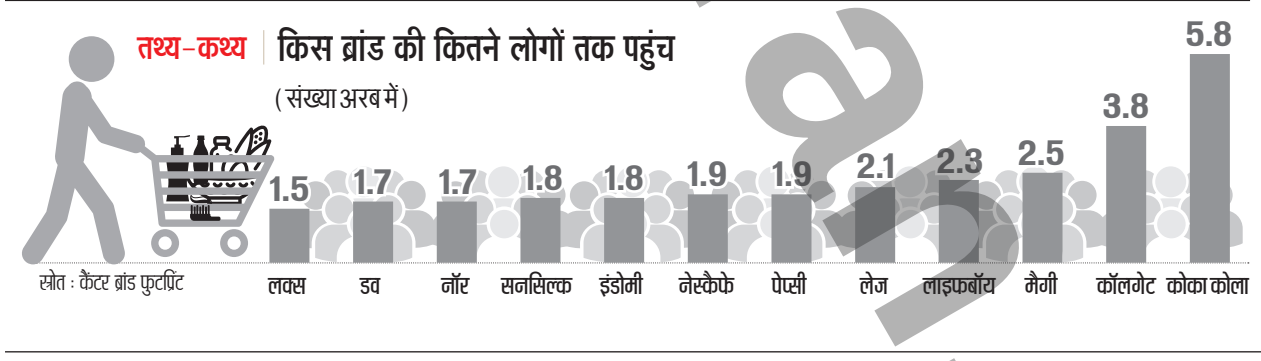

स्रोत : कैंटर ब्रांड फुटप्रिंट

रद हुई छुट्टियां

राजरंग

उपलब्धियों के चार साल की तैयारियों को लेकर बीता पखवाड़ा कई मंत्रालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों पर भारी पड़ा। उनकी छुट्टियां रद हो गईं। सारा अमला सरकार का कामकाज गिनाने में लगा दिया गया। सबकी ड्यूटी बिना नागा लगा दी गई। कृषि मंत्रालय में कर्मचारी और अधिकारी इसी काम में व्यस्त थे। हर कोई चार साल से जुड़े आयोजनों में व्यस्त था। कई अफसरों पर आफत आन पड़ी। गर्मियों की छुट्टियों के लिए पहले से ही टिकट करा चुके कई कर्मचारियों को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दफ्तर में छुट्टियों के लिए साहब से झक लड़ानी पड़ी तो घर में पत्नी व बच्चों को समझाने की जद्दोजहद से कर्मचारी जूझते रहे। छुट्टियों के लिए नायाब तरीके के बहाने भी काम नहीं आए। सरकार के चार साल पूरे होने पर सबसे ज्यादा सुकून इन कर्मचारियों को मिला है, लेकिन घर में सुकून अभी भी नहीं है।

माया मिली ना राम

सूचना व प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने सभी को फिट रहने का संदेश क्या दिया देश भर में अपने आपको फिट व तंदरुस्त साबित करने वालों में होड़ मच गई है। कैबिनेट के कुछ मंत्रियों ने भी राठौड़ की चुनौती को स्वीकार करते हुए कसरत करते हुए वीडियो ट्वीट किए हैं, लेकिन हद तो तब हो गई है जब कुछ मंत्रियों के स्टाफ भी इस होड़ में शामिल होने लगे। एक मंत्री के वरिष्ठ सहयोगी स्टाफ जिन्होंने शायद ही कभी कोई वर्जिश की हो, ने दफ्तर में कसरत करते हुए जो वीडियो बनवाया उसमें उनकी कमर की हड्डी चटक गई। यह महाशय उसके बाद भी अपनी वीडियो डालने के लिए परेशान थे। अपने सहयोगियों को वह बोल रहे थे 'यार कमर तो टूट ही गई, कम से कम वीडियो तो डाल ही दो।' लेकिन यह हो नहीं सका।

गंगा से लगाव

गंगा महकमे की मंत्री रहते हुए उमा भारती ने भले ही इसकी कोई चिंता न की हो, लेकिन आजकल वह गंगा से लगाव दिखाने का कोई भी मौका नहीं चूकतीं। हाल ही में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने पत्रकारों को बातचीत के लिए बुलाया। आधिकारिक तौर पर सूचना आई कि सिर्फ गडकरी ही मीडिया से बात करेंगे, लेकिन जब पत्रकारों से खचाखच भरे हॉल में अचानक से उमा की एंट्री हुई तो सब लोग बगलें झांकने लगे। सिर्फ पत्रकार ही नहीं कई अधिकारियों के चेहरे के हावभाव यह बता रहे थे कि शायद उनको भी गंगा की पूर्व मंत्री के आने का अंदाजा नहीं था। बहरहाल लोगों ने उनसे सवाल तो नहीं पूछे, लेकिन जैसा फीडबैक दिया उससे शायद उन्हें अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का अहसास हो गया होगा।

मंत्री बनने का असर

विपक्ष में रहने पर शोर और सत्ता में बैठते ही हर दल के एक सुर का राज क्या है? यह है जिम्मेदारी और सामंजस्य का दबाव। मोदी सरकार में ही एक मंत्री जी का शुरुआती काल लेबर यूनियन के संपर्क में बीता था। लिहाजा हर बात में कहीं न कहीं वह भाव आ ही जाता था। जब वह केंद्र में मंत्री बने और संयोगवश उन्हें श्रम मंत्रालय भी दे दिया गया तो परेशानी खड़ी हो गई। श्रम सुधार के कई विषय आए जिसमें वह इकतरफा नहीं सोच सकते थे। सचिव का कुछ और मानना होता, मंत्री जी कुछ और तर्क देते। सचिव समझाते कि हमें उद्योगों का भी सोचना होगा तो वह कहते- लेकिन इसमें तो श्रमिकों का नुकसान हो जाएगा। आखिरकार उन्हें अहसास दिलाया गया कि वह यूनियन में नहीं, सरकार में बैठे हैं और उन्हें हर वर्ग के बीच तालमेल बिठाना होगा तब कहीं जाकर वह जागे और फाइल पर हस्ताक्षर किया।

ट्वीट-ट्वीट

इन दिनों राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटना सबसे आसान काम है। अगर मैं आपसे सहमत नहीं हूं तो मैं देशद्रोही हूं। ऐसे सर्टिफिकेट अपने पास ही रखें मुझे उनकी जरूरत नहीं।
यशवंत सिन्हा@YashwantSinha

अपने हीरो राशिद खान पर हम फख्र करते हैं। मैं भारतीय दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने उसको अपनी प्रतिभा प्रदर्शन के लिए माकूल मंच दिया। राशिद अफगानों की अकूत संभावनाओं को दर्शाते हैं। वह क्रिकेट की दुनिया के अनमोल रत्न हैं और हम यह हीरा किसी को नहीं देने जा रहे।
अशरफ गनी@ashrafghani

जिंदगी परीक्षा में मिले नंबरों से कहीं बढ़कर है। हर बच्चा अपने आप में खास है और परीक्षा के अंक ही उसके भविष्य के एकमात्र निर्धारक नहीं हैं। एक अभिभावक के तौर पर कृपया अंकों से परे सोचें। आपके बच्चे ने जो हासिल किया उस पर उसे थपकी दें और गले लगाएं वही उसका सबसे बेहतरीन परिणाम होगा।
वीरेंद्र सहवाग@virendersehwag

मोदी सरकार की चार साल की उपलब्धियों में अंकटाड की रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है कि एफडीआइ आकर्षित करने में वह दुनिया के तीन शीर्ष देशों में शुमार है, लेकिन यह स्थिति तो पिछले एक दशक से ही बनी हुई है।
रूपा सुब्रमण्या@rupasubramanya

जनपथ

सत्ता आई हाथ में गए बरस भी चार,
ज्यादातर संतुष्ट हैं असंतुष्ट दो-चार।
असंतुष्ट दो-चार रही यदि कोशिश जारी,
पक्का मानो आप मिलेगी फिर इक पारी।
ऊँचा रखिए आप सिर्फ भारत का मत्था,
तो सौंपेगा देश जानिए फिर से सत्ता।
– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, **E-mail: delhi@nda.jagran.com,** R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। **वर्ष 28 अंक 312**